राज्य स्तरीय बैकर्स समिति (उ. प्र.) की दिनांक 21.02.2014 को सम्पन्न बैठक का कार्यवृत्त

राज्य स्तरीय बैकर्स समिति (उ. प्र.) की दिसम्बर 2013 त्रैमास की समीक्षा बैठक दिनांक 21.02.2014 को "महाराजा सयाजीराव गायकवाड सभागार", बड़ौदा हाउस, गोमती नगर, लखनऊ में सम्पन्न हुई जिसकी अध्यक्षता श्री पी. श्रीनिवास, कार्यकारी निदेशक, बैंक ऑफ बड़ौदा, मुम्बई द्वारा की गयी।

बैठक में श्री आर. एम. श्रीवास्तव, आई.ए.एस, प्रमुख सचिव (संस्थागत वित्त); श्री देवाशीष पाण्डा, आई.ए.एस, प्रमुख सचिव (कृषि); डा0 आदर्श सिंह, आई.ए.एस, मिशन निदेशक, (एन.आर.एल.एम.), उ.प्र. शासन, लखनऊ; श्री अरुण पसरीचा, क्षेत्रीय निदेशक, भारतीय रिजर्व बैंक, लखनऊ; श्री के के गुप्ता, मुख्य महाप्रबन्धक, नाबार्ड, लखनऊ व श्री शिव सिंह यादव, निदेशक, संस्थागत वित्त निदेशालय, उत्तर प्रदेश शासन विशेष रुप से उपस्थित रहे। साथ ही विभिन्न बैंको/वित्तीय संस्थाओ के वरिष्ठ कार्यपालकों तथा राज्य व केन्द्र सरकार के उच्चाधिकारियों ने भी इस बैठक मे सहभागिता की। भाग लेने वाले अधिकारियों की सूची संलग्न है।

बैठक के प्रारम्भ में श्री निर्मेष कुमार, महाप्रबन्धक, बैंक ऑफ बड़ौदा एवं संयोजक राज्य स्तरीय बैंकर्स समिति (उ.प्र.) ने श्री पी. श्रीनिवास, कार्यकारी निदेशक, बैंक ऑफ बड़ौदा; श्री आर. एम. श्रीवास्तव, आई.ए.एस, प्रमुख सचिव (संस्थागत वित्त); श्री देवाशीष पाण्डा, आई.ए.एस, प्रमुख सचिव (कृषि); डा0 आदर्श सिंह, आई.ए.एस, मिशन निदेशक, (एन.आर.एल.एम.), उ.प्र. शासन, लखनऊ; श्री अरुण पसरीचा, क्षेत्रीय निदेशक, भारतीय रिजर्व बैंक, लखनऊ; श्री के के गुप्ता, मुख्य महाप्रबन्धक, नाबार्ड, लखनऊ; श्री शिव सिंह यादव, निदेशक, संस्थागत वित्त निदेशालय, उत्तर प्रदेश शासन व बैठक में पधारे अन्य गणमान्य अतिथियों का स्वागत करते हुये निम्न महत्वपूर्ण बिन्दुओं पर प्रकाश डाला :-

- भारतीय रिजर्व बैंक के निर्देशानुसार राज्य स्तरीय बैंकर्स समिति उ.प्र. की तिमाही बैठको का वार्षिक कैलेण्डर सभी सम्बन्धित को प्रेषित किया जा चुका है। तदनुसार विभिन्न गतिविधियों हेतु बैंको के स्तर से समयबद्ध कार्यवाही का अनुरोध है।
- उन्होने मार्च 2014 तक प्रदेश में -3000- नयी बैंक शाखाओ की स्थापना एवं -12- चयनित जनपदों में 3% प्वाइंट तक ऋण जमा अनुपात को बढ़ाने (मार्च 2013 के स्तर से) जैसे -2- महत्वपूर्ण बिन्दुओ पर प्रकाश डालते हुये सदन को अवगत कराया कि 19.02.2014 तक प्रदेश में बैंको द्वारा -1571- नयी बैंक शाखायें स्थापित की गयी है जो 3000 लक्ष्य के सापेक्ष -1429- कम है जिसकी पूर्ति आगामी लगभग 50 दिनो की अवधि में किया जाना अपेक्षित है। प्रदेश में चयनित -12- जनपदो में से -10- जनपदों में, सभी बैंको के सम्मिलित प्रयासों से ऋण जमा अनुपात में व्यापक वृद्धि दर्ज की गयी है।

  उन्होने यह भी अवगत कराया कि शाखा विस्तार कार्यक्रम की समीक्षा हेतु क्षेत्रीय निदेशक, भारतीय रिजर्व बैंक, लखनऊ द्वारा दिनांक 23.01.2014 को एक विशेष बैठक आयोजित की

गयी थी। साथ ही निदेशक, संस्थागत वित्त द्वारा भी मासिक आधार पर इसकी समीक्षा की जा रही है। सचिव (वित्तीय सेवाये), वित्त मंत्रालय, भारत सरकार ने बैंक ऑफ बड़ौदा के अध्यक्ष एवं प्रबन्ध निदेशक को सम्बोधित पत्र द्वारा प्रदेश में नयी बैंक शाखायें खुलने की धीमी प्रगति पर चिंता व्यक्त की है।

- 2000 से कम आबादी वाले गावों मे वित्तीय समावेशन कार्यक्रम के सफलतापूर्वक क्रियान्वयन के विषय में चर्चा करते हुये महाप्रबन्धक महोदय ने बताया कि बैंको को चयनित सभी -76855- गावों में बैंकिंग सेवाओ का विस्तार अगले -3- वर्षो में मार्च 2016 तक चरणबद्ध तरीके से करना है। इसके अंतर्गत पहले वित्तीय वर्ष 2013-14 के लक्ष्य -30515- के सापेक्ष दिसम्बर 2013 तक -11242- गॉव कवर हुये है जोकि लक्ष्य का 37% है।
- इसी क्रम में उन्होने अवगत कराया कि भारतीय रिजर्व बैंक, केन्द्रीय कार्यालय, मुम्बई द्वारा भी बैंक ऑफ बड़ौदा के अध्यक्ष एवं प्रबन्ध निदेशक को सम्बोधित पत्र द्वारा वित्तीय समावेशन कार्यक्रम के अंतर्गत प्रदेश मे दर्ज धीमी प्रगति पर गम्भीर चिंता व्यक्त की गयी है।
- उन्होने प्रदेश सरकार से बैंकर्स की ओर से ऋण वसूली, सुरक्षा एवं व्यवसाय वृद्धि हेतु आधारभूत सुविधाओं के विस्तार आदि महत्वपूर्ण बिन्दुओ पर सक्रिय सहयोग का अनुरोध करते हुये कहा कि निश्चय ही, भविष्य में यह निरंतर सहयोग और बेहतर उपलब्धियाँ प्रदान करेगा।

अपने सम्बोधन के अन्त में श्री निर्मेष कुमार, महाप्रबन्धक, बैंक ऑफ बड़ौदा एवं संयोजक राज्य स्तरीय बैंकर्स समिति (उ.प्र.) ने सभी सम्बन्धित विभाग प्रमुखो, बैंको व अन्य कार्यदायी संस्थाओं से आग्रह किया कि वे प्रदेश के विकास हेतु किये जा रहे कार्यो व उपलब्धियो से सम्बन्धित सुसंगत आकड़ो का ससमय प्रेषण सुनिश्चित करें ताकि प्रदेश की उपलब्धियो को और प्रभावी रुप से प्रस्तुत किया जा सके।

अपने अध्यक्षीय सम्बोधन में श्री पी. श्रीनिवास, कार्यकारी निदेशक, बैंक ऑफ बड़ौदा ने सभी अतिथियों का स्वागत व अभिनन्दन करते हुये निम्न बिन्दुओं पर प्रकाश डाला :-

- आलोच्य अवधि के दौरान प्रदेश मे विभिन्न मानको के अंतर्गत अच्छी प्रगति दर्ज हुई है। साथ ही कुछ ऐसे क्षेत्र भी है जहॉ अपेक्षित परिणाम प्राप्त नहीं हो सके है जिसके अनुरुप प्रभावी कार्यवाही अपेक्षित है।
- गत 15.01.2013 को सम्पन्न विशेष एस.एल.बी.सी. बैठक के -2- प्रमुख निर्णयों यथा -3000- नई बैंक शाखाओं की स्थापना एवं -6- लीड बैंको से सम्बन्धित -12- चयनित जनपदों में मार्च 2014 तक 3% प्वाइन्ट ऋण जमा अनुपात की वृद्धि का स्मरण कराते हुये उन्होने प्रदेश में शाखा विस्तार की दिसम्बर 2013 माह तक की धीमी प्रगति पर चिंता व्यक्त की। उन्होने कहा कि यह मुद्दा भारत सरकार द्वारा उच्चतम स्तर पर चर्चा का विषय है तथा इसकी प्रगति समीक्षा नियमित रुप से की जा रही है। इस विषय पर कुछ क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों के लाइसेंस से सम्बन्धित प्रकरण का संज्ञान लेते हुये उन्होने अन्य प्रमुख बैंको से आह्वाहन किया कि वे अपने निर्धारित लक्ष्यों की शत-प्रतिशत पूर्ति सुनिश्चित करें।

- ऋण जमा अनुपात के विषय में अध्यक्ष महोदय ने जहाँ -12- में से -10- चयनित जनपदों द्वारा दर्ज वृद्धि की सराहना की, वहीं प्रदेश में ऋण जमा अनुपात में विगत त्रैमास की अपेक्षा 0.82% की हुई गिरावट पर चिंता व्यक्त की।
- वार्षिक ऋण योजना 2013-14 के अंतर्गत दिसम्बर 2013 त्रैमास तक दर्ज 60.55% प्रगति का जिक्र करते हुये श्री श्रीनिवास, कार्यकारी निदेशक, बैंक ऑफ बड़ौदा ने कहा कि यद्यपि यह उपलब्धि गत वर्ष की समान अवधि के सापेक्ष कुल ऋण वितरण धनराशि व प्रतिशत मानकों में अधिक रही है तथापि आवश्यकता इस बात की हैं कि शेष 40% लक्ष्यों की पूर्ति मार्च 2014 तक करते हुये निर्धारित लक्ष्यो की शतप्रतिशत पूर्ति सुनिश्चित की जाये। इसके लिये विशेषकर क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों द्वारा सक्रिय योगदान की आवश्यकता है।
- प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्र के विभिन्न घटकों यथा –कृषि ऋण, कमजोर वर्गों को ऋण व अल्प संख्यक समुदाय को प्रदत्त ऋण की प्रगति के विषय में उन्होने कहा कि इन क्षेत्रो में प्रदेश की प्रगति भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा निर्धारित मानकों से अधिक है जोकि सराहनीय है। तथापि कृषि क्षेत्र में ऋण प्रवाह को बढ़ाने हेतु निवेश ऋण (Investment Credit) को बढ़ाने की आवश्यकता है। उत्तर प्रदेश जैसे कृषि प्रधान राज्य में निवेश ऋण की प्रचुर सम्भावनाऐं है जिसका सदुपयोग कर हमें प्रदेश के कृषि ऋण पोर्टफोलियो को नवीनतम उचाँई तक पहुँचाना है।
- वित्तीय समावेशन के अंतर्गत 2000 से अधिक आबादी वाले -16388- गावों में बैंकिग सेवाओ के विस्तार का कार्य बैंको द्वारा सफलतापूर्वक सम्पन्न कर लिया गया है। इसी क्रम में 2000 से कम आबादी वाले -76855- गावों मे मार्च 2016 तक बैंकिग सेवाओ के विस्तार हेतु भी रोडमैप तैयार किया गया है जिसके अनुरुप मार्च 2014 तक का लक्ष्य -30515- गॉवो मे बैंकिंग सेवाऐ प्रदान करने का था। इस लक्ष्य के सापेक्ष दिसम्बर 2013 तक की प्रगति के अनुसार मात्र -11242- गॉव कवर हो पाये है, जो असंतोषजनक है। उन्होने इस विषय पर भारतीय रिजर्व बैंक, केन्द्रीय कार्यालय, मुम्बई द्वारा बैंक ऑफ बड़ौदा के अध्यक्ष एवं प्रबन्ध निदेशक को सम्बोधित पत्र का जिक्र करते हुये सभी बैंको से मार्च 2014 तक निर्धारित लक्ष्यो के सापेक्ष शतप्रतिशत उपलब्धि प्राप्त करने हेतु आह्वाहन किया।
- उन्होने डी.बी.टी. एवं डी.बी.टी.एल. योजना के अंतर्गत चयनित क्रमश: -6- एवं -3- जनपदों में सभी लाभयार्थियों का बैंक खाता खोलने तथा विशेषकर खाते से आधार संख्या लिंक करने के निर्धारित कार्य को शीघ्रता से पूर्ण किये जाने की आवश्यकता पर बल दिया ताकि इस योजना का सफलतापूर्वक क्रियान्वयन हो सके।
- ए.टी.एम. के सम्बन्ध में चर्चा करते हुये अध्यक्ष महोदय ने भारत सरकार के दिशानिर्देशों को दोहराते हुये कहा कि सभी बैंक शाखाओं के साथ एक ऑन-साइट ए.टी.एम. का होना अनिवार्य है तथा बैंको को यह कार्य 31.03.2014 तक पूर्ण करना है। उन्होने सभी बैंको से अपील की कि वह सभी पात्र किसान क्रेडिट कार्ड धारको को डेबिट कम ए.टी.एम. कार्ड (रुपे कार्ड) तथा अन्य ग्राहकों को ए.टी.एम. कार्ड की सुविधा भी अवश्य उपलब्ध कराये ताकि ए.टी.एम. मशीनो का व्यापक उपयोग हो सके जिससे कि बैंको की लाभप्रदत्ता में वृद्धि हो तथा बेहतर ग्राहक सेवा प्रदान की जा सके।

- बुनकर क्रेडिट कार्ड के विषय में उन्होने कहा कि सभी प्राप्त आवेदनों का "कैम्प मोड" में शाखा स्तर पर निस्तारण 10.03.2014 तक किया जाना चाहिये ताकि आवंटित लक्ष्यों के सापेक्ष अच्छी प्रगति प्राप्त की जा सके।
- **स्वयं सहायता समूहों के विषय में अध्यक्ष महोदय ने कहा कि प्रदेश में 1,25,000 स्वयं** सहायता समूहों को क्रेडिट लिंक करने के लक्ष्य के सापेक्ष अभी तक 20000 समूहो को बैंको द्वारा क्रेडिट लिंक किया जा सका है। उन्होने बैंको से इस सन्दर्भ में विशेष ध्यान देने का आह्वाहन करते हुये कहा कि आने वाले दिनों मे सभी समूह "राष्ट्रीय ग्रामीण आजिविका मिशन" के अंतर्गत आच्छादित किये जायेगे तथा इन समूहों को पात्रता के अनुसार **Interest Subvention** का लाभ मिलेगा, जो बैंको की ऋण वसूली में सहायक सिद्ध होगा। साथ ही उन्होने विभिन्न सरकार प्रायोजित कार्यक्रमो में भी बैंकों द्वारा अधिकतम योगदान प्रदान करने हेतु कहा।
- आरसेटी संस्थानों हेतु राज्य सरकार द्वारा प्रदेश के -65- जनपदो में नि:शुल्क भूमि का आवंटन हो चुका है। सम्बन्धित बैंको द्वारा इन सभी स्थानो पर लीजडीड निष्पादित करते हुये भूमि पर भौतिक कब्जा करने के उपरान्त, भवन निर्माण की प्रक्रिया यथा शीघ्र प्रारम्भ की जाये ताकि यथाशीघ्र योजनांतर्गत वांछित उपलब्धियां हासिल की जा सके। सभी बैंको को अपने सम्बन्धित आरसेटी संस्थानो की "ए" ग्रेडिंग के लिये प्रयासरत रहना चाहिये। उन्होने प्रदेश सरकार से अनुरोध किया कि शेष 10 जनपदों मे भी भूमि आवंटन अतिशीघ्र कराया जाये।
- प्रदेश में बैक ऋण वसूली की स्थिति का जिक्र करते हुये उन्होने राज्य सरकार से वांछित सहयोग का अनुरोध किया। उन्होने कहा कि इस वर्ष प्रदेश में अच्छी फसल होने के कारण यहाँ ऋण वसूली की बेहतर सम्भावनाऐं है। बैंको एवं राज्य सरकार के सहयोग से निश्चय ही उत्साहवर्धक परिणाम परिलक्षित होगें जिससे भविष्य में बैंको का मनोबल बढ़ेगा तथा वह पूरे वर्ष उत्साहवर्धक ऋण वितरण का कार्य करने हेतु प्रेरित करेंगे।

अपने अध्यक्षीय सम्बोधन के अंत में श्री पी. श्रीनिवास, कार्यकारी निदेशक, बैंक ऑफ बड़ौदा ने विश्वास व्यक्त किया कि प्रदेश में वियमान अच्छे माहौल में बैंक व राज्य सरकार के संयुक्त प्रयासों से विकास प्रक्रिया को नयी दिशा व गति प्राप्त होगी।

श्री आर.एम. श्रीवास्तव, आई.ए.एस, प्रमुख सचिव (संस्थागत वित्त), उ. प्र. शासन ने सदन को सम्बोधित करते हुए सभी बैंको द्वारा प्रदेश में संचालित विभिन्न कार्यक्रमों में समुचित प्रयास करने का आग्रह किया। उन्होने कहा कि इस वित्तीय वर्ष की समाप्ति मे केवल एक माह का समय ही शेष रह गया है। अत: हम सभी को एक जुट होकर प्रदेश के विकास में योगदान करने की आवश्यकता है। इसी क्रम में बैंको द्वारा -3000- नयी शाखाओ की स्थापना के विषय में जहाँ एक ओर उन्होने -7- बैंको एवं -5- जनपदो के अग्रणी जिला प्रबन्धकों को उनके लक्ष्य की पूर्ति के लिये शुभकामनायें दी वहीं दूसरी ओर -17- प्रमुख बैंको द्वारा लक्ष्य की पूर्ति के लिये लगभग -1432- नयी शाखाऐं और खोले जाने हेतु आह्वाहन किया। उन्होने सदन को अवगत कराया कि इस विषय पर विस्तृत चर्चा के लिये प्रदेश सरकार ने सभी सम्बन्धित बैंको एवं विभागों की बैठक का आयोजन 22.02.2014 को मुख्य सचिव, उ.प्र. शासन की अध्यक्षता में किया है। उन्होने सभी